(b) if so, when a decision is likely to be taken in the matter ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. R. GANESH) : (a) and (b). No, Sir. The LIC's "Property Mortgage" Scheme and "Own Your Home" Scheme, which provide loan finance for housing, have been extended to all centres where it has either a branch office or a sub-office, irrespective of the population. At some centres the population is even less than 10000. The Scheme are also in operation at a few other selected centres where the LIC does not have any office. The total number of centres where the Schemes are in operation is 423.

आर्थिक कार्य विभाग में अनुभाग अधिकारी, हिन्दी अनुवादक और हिन्दी सहायक

2629. **श्री बन्शपाल सैलानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के हिन्दी अनुभाग में अनुभाग अधिकारियों, हिन्दी अनुवादकों और हिन्दी सहायकों की संख्या कितनी है ;

(ख) उक्त पदों के लिए भर्ती और पदोन्नति की पद्धति क्या है ;

(ग) उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या कितनी है ; और

(घ) अगर उपर्युक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक हो तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) हिन्दी अनुभाग में कर्मचारियों की स्थिति इस प्रकार है :

(i) अनुभाग अधिकारी 2

(ii) हिन्दी अनुवादक 10

(iii) हिन्दी सहायक 7

(ख) (i) **अनुभाग अधिकारी** : विभाग में अनुवादक पदक्रम (ग्रेड) में 5 वर्ष की सेवा वाले अनुवादकों की पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति पर अन्तरण द्वारा, ऐसा भी न होने की स्थिति में सीधी भर्ती द्वारा ।

(ii) **हिन्दी अनुवादक** : वित्त मंत्रालय में काम करने वाले और फिलहाल हिन्दी सहायक के पद पर कार्य करने वाले ऐसे व्यक्तियों के अन्तरण द्वारा जिन्होंने हिन्दी सहायक (पदक्रम 210—530 रुपये) के रूप में कम से कम 3 वर्ष काम किया हो, ऐसा न होने की स्थिति में सीधी भर्ती द्वारा ।

(iii) **हिन्दी सहायक** : चूंकि सरकार ने इन पदों को समाप्त करने और इनके बदले अनुवादकों के पद बनाने का फैसला किया है इसलिए इन पदों के सम्बन्ध में भर्ती के कोई नियम नहीं बनाए गए हैं। वर्तमान पदधारियों को अखिल सचिवालयिक आधार पर, हिन्दी जानने वाले उच्च श्रेणी लिपिकों और निम्न श्रेणी लिपिकों में से चुना गया था ।

(ग) कोई नहीं ।

(घ) अनुभाग अधिकारी पद क्रम के मामले में आरक्षण सम्बन्धी आदेश लागू नहीं होते क्योंकि इन्हें पदोन्नति द्वारा भरा गया है। जहां तक अनुवादकों का सम्बन्ध है, ऐसे हिन्दी सहायक, जिन्हें पदोन्नत करके अनुवादक बनाया गया है, शुरू में संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती किये गये थे और गृह मंत्रालय द्वारा नामित किए गए थे। उस मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के किसी हिन्दी सहायक को आर्थिक कार्य विभाग में नामित नहीं किया गया था। हिन्दी सहायकों के मामले में, तदर्थ नियुक्तियां, अखिल सचिवालयिक आधार पर, हिन्दी जानने वाले उच्च श्रेणी लिपिकों और निम्न श्रेणी लिपिकों में से की गयी है। ये पूर्णतः तदर्थ नियुक्तियां हैं क्योंकि गृह मंत्रालय के वर्तमान अनुदेशों के अनुसार हिन्दी सहायकों के पद समाप्त किये

जाने हैं और इनके स्थान पर हिन्दी अनुवादकों के पदों का निर्माण किया जाना है। इस सम्बन्ध में कार्रवाई की जा रही है और जब भर्ती के नियम बन जायेंगे, तो पदों को नियमित आधार पर भरा जायगा और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों के लिए प्रारक्षण सम्बन्धी आदेशों का पालन किया जायगा।

Recognition to National Diploma in Commerce for Admission to M.B.A. Course

2630. SHRI KINDER LAL : Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) whether the Delhi University has withdrawn from this year the recognition of Government of India's National Diploma in commerce course for admission to Master of Business Administration course, if so, the reasons therefor ;

(b) the reasons for certain restrictions being imposed by Delhi University on Government of India's National Diploma holders for admission to Post-Graduate courses ;

(c) whether Aligarh University has sent a scheme for government's approval for starting Correspondence course at Post-Graduate level for National Diploma holders, if so, whether Government propose to implement it early ; and

(d) how Government propose to find a solution for further studies in Post-Graduate courses by National Diploma (Commerce) students at the Delhi University ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF CULTURE (SHRI D. P. YADAVA) : (a) The Delhi University had at no time recognised the National Diploma in Commerce for admission to the Master's Degree Course in Business Administration. Therefore, the question of withdrawal of the recognition does not arise.

(b) The University has not considered the National Diploma in Commerce as academically equivalent to its B. Com. degree for the purpose of admission to the M. Com. Course. The University, however, under a temporary Ordinance (1968) made a special provision for the holders of the National Diploma in Commerce to either appear for the B. Com. degree examination of the University or to sit for an entrance test for admission to the M. Com. course, after undergoing a course of instruction of two academic terms in both cases.

(c) No specifi scheme has been received from the University. The proposal is still under the consideration of the University.

(d) A number of Indian universities have recognised the National Diploma as equivalent to their B. Com degree for purpose of admission to postgraduate courses in commerce. National Diploma holders can seek admission to these universities for continuing their studies for the M. Com. degree.

Finance Allocation for Prohibition Programme in U. P.

2631. SHRI K. C. PANDEY : Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state the amount allotted by the Central Government for prohibition during the Fourth Plan period for U.P. ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE (SHRI K. S. RAMASWAMY) : As per entry 8 of List II of the Seventh Schedule to the Constitution, the prohibition programme and its implementation fall in sphere of the responsibility of State Governments, and as such no amount has been allotted by the Central Government to U. P. in this regard under Plan provision.

Development of Places of Tourist Interest in Rajasthan

2632. SHRI BRIJ RAJ SINGH-KOTAH : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state the steps taken up by Government for the development of places of tourist interest in Kota and its environment in Rajasthan and futher plans in this regard ?